भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोकसभा

तारांकित प्रश्न सं. *312

(जिसका उत्तर सोमवार 11 अगस्त, 2025 /20 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है)

घरेलू ऋण में वृद्धि

***312. सुश्री सयानी घोष:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को घरेलू ऋण में कथित वृद्धि की जानकारी है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पाँच वर्षों के दौरान उक्त ऋण संबंधी प्रवृत्तियों का ब्यौरा क्या है तथा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में परिवारों की घरेलू वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बढ़ते खुदरा ऋण और घटती शुद्ध घरेलू वित्तीय बचत से उत्पन्न संभावित जोखिमों का आकलन किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा अधिक मात्रा में घरेलू ऋण के जोखिम की निगरानी और उसे कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या परिवारों की वित्तीय स्थिति को प्रभावित किए बिना सतत ऋण वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए किसी विशिष्ट उपाय पर विचार किया जा रहा है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार की खपत की समग्र माँग और आर्थिक विकास के संबंध में अध्ययन कराने की कोई योजना है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्री

(श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

घरेलू ऋण में वृद्धि के विषय में सुश्री सयानी घोष द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *312 के संबंध में 11 अगस्त 2025 को दिए जाने वाले उत्तर से संदर्भित विवरण

(क) और (ख): सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में घरेलू वित्तीय आस्तियों और देनदारियों के स्टॉक के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों का वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 1: घरेलू वित्तीय आस्तियों और देनदारियों का स्टॉक (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)					
	मार्च-20	मार्च -21	मार्च -22	मार्च -23	मार्च -24
वित्तीय आस्तियाँ	85.5	115.2	107.8	103.5	106.2
वित्तीय देनदारियाँ	34.7	39.1	36.5	38	40.2

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई)

मार्च 2020 से मार्च 2024 तक घरेलू वित्तीय देनदारियों के स्टॉक में लगभग 5.5 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि के दौरान घरेलू वित्तीय आस्तियों के स्टॉक में 20.7 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है। इस प्रकार, 2023-24 तक परिवारों की निवल वित्तीय स्थिति (आस्तियों के स्टॉक में से देनदारियों के स्टॉक को घटाकर) में सुधार हुआ है।

(ग): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बैंकों के खुदरा ऋणों की पैठ (गैर-बैंक के बैंक में विलय के समायोजन के बाद सकल ऋण और अग्रिम के प्रतिशत के रूप में खुदरा ऋण) मार्च 2024 में 30.94% थी जो मामूली रूप से बढ़कर मार्च 2025 में 31.48% हो गई है। हालांकि, खुदरा ऋणों में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि की गति मार्च 2024 में 17.61% से घटकर मार्च 2025 में 14.05% हो गई है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के खुदरा ऋण खंड में आस्ति की गुणवत्ता काफी हद तक स्थिर होने के साथ मार्च 2025 तक सकल गैर-निष्पादित आस्तियों का अनुपात 1.18 प्रतिशत है। इसके अलावा, गैर-जमानती खुदरा ऋणों का अंश अपेक्षाकृत कम है और यह खुदरा ऋणों का 25 प्रतिशत तथा कुल सकल अग्रिमों का 8.3 प्रतिशत है। इसके अलावा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा प्रकाशित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, निवल घरेलू वित्तीय बचत 2022-23 में ₹13.3 लाख करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹15.5 लाख करोड़ हो गई है। इसलिए, भारतीय बैंकों की आस्ति गुणवत्ता के लिए इसके व्यवस्थागत चिंता का विषय होने की संभावना नहीं है।

(घ) और (ङ): आरबीआई द्वारा प्रकाशित वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (जून 2025) के अनुसार, बकाया राशि और उधारकर्ताओं की संख्या दोनों के संदर्भ में प्राइम और इससे अधिक की रेटिंग वाले उधारकर्ताओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है। यह समग्र स्तर पर प्रतिरोधक घरेलू बैलेंस शीट का संकेत देता है। तथापि, खुदरा ऋण खंड में देखी गई सुदृढ़ वृद्धि को देखते हुए, विनियामक दृष्टिकोण से, आरबीआई ने वित्तीय प्रणाली की प्रतिरोधकता को सुदृढ़ करने के एक सावधानीपूर्वक किए गए उपाय के रूप में, नवंबर 2023 में उपभोक्ता ऋण और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को बैंक ऋण के चुनिंदा खंडों पर जोखिम भार में सुधार किया। इसके परिणामस्वरूप, गैर-जमानती खुदरा ऋण खंड में ऋण वृद्धि (सीएजीआर) सितंबर 2021-23 के बीच 27.0 प्रतिशत से कम होकर सितंबर 2023 - मार्च 2025 के बीच 11.6 प्रतिशत हो गई है। इसके अतिरिक्त, ब्याज दरों में चल रही कमी और नकदी से विकास को बढ़ावा मिलने और परिवारों के ऋण की अदायगी के भार के कम होने की संभावना है। ₹12 -12.75 लाख तक की वार्षिक आय के लिए नई आयकर छूट से मध्यम वर्ग के लिए प्रयोज्य आय में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे इन परिवारों को ऋण का बेहतर प्रबंधन करने में सहायता मिल सकती है। इन सबसे बढ़कर, व्यापार में सुगमता, कौशल विकास, रोजगार सृजन और अवसंरचना के निर्माण पर सरकार का ध्यान आय में वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है।

(च): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय परिवारों के उपभोग पैटर्न और व्यय/मांग को समझने के लिए नियमित अंतराल में घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) करता है। हालिया एचसीईएस सर्वेक्षण अगस्त 2023 - जुलाई 2024 के दौरान किया गया था। इसके साथ ही, वित्त मंत्रालय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है जो वृहद-आर्थिक रुझानों और आर्थिक विकास पर वार्षिक जानकारी प्रदान करता है।

***